दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17–M–**GS2**

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Chetan Kumar meena

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date):

रोल न. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	2	5	4	8	0	8

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): Hindi

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Cm

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

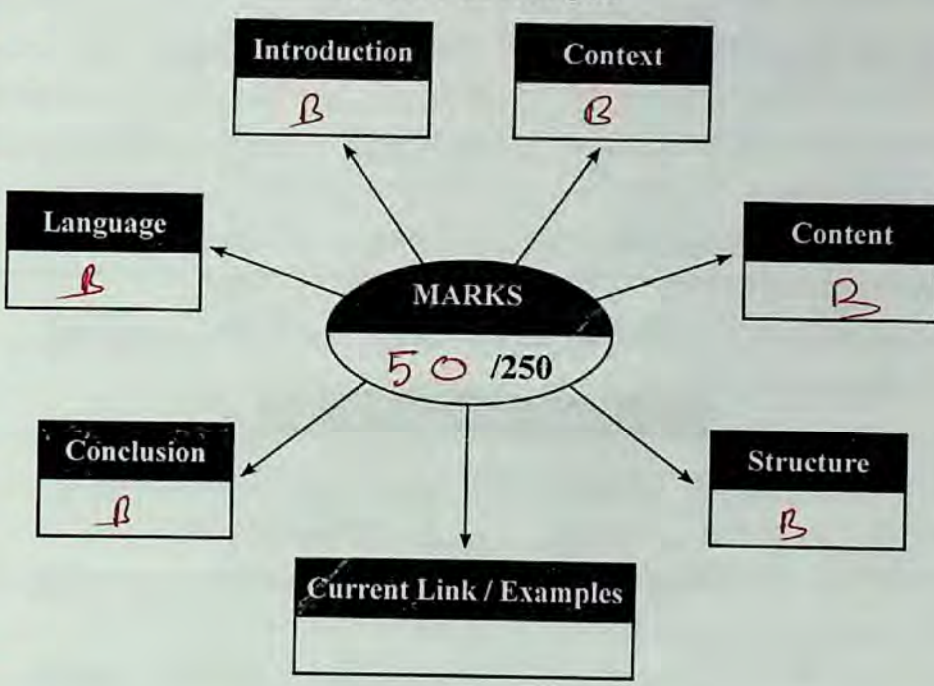

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- सभी प्रश्न हल करने का प्रयास करें

- विषय वस्तु और उन्नत करने का प्रयास करें।

- प्रश्न के सभी पक्षों को हल करने का प्रयास करें।

-

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इ
संख्या व
न लिखें

(Please
anything
question
this spac

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज़' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

नागरिक समाज की अभिव्यक्ति को सरकार तक पहुँचाने तथा सरकार की योजनाओं व नीतियों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा कर जनता तक उसकी समीक्षा पहुँचाने के कारण मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया की भूमिका सरकार को जनोन्मुखी बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है।

लोकतंत्र के अन्य स्तंभों का भी उल्लेख करें

किन्तु वर्तमान में मीडिया का विकृत स्वरूप 'पेड-न्यूज' के रूप में जाना जा रहा है। 'पेड-न्यूज' के कारण सरकार की वस्तुनिष्ठ समीक्षा जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, चुनाव से पूर्व भ्रामक सर्वेक्षण द्वारा जनमत की राय को

पेड-न्यूज क्या है स्पष्ट करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आज मीडिया का प्रयोग अलोकप्रिय नेताओं की छवि चमकाने तथा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचाने में किया जा रहा है।

पेड न्यूज के कारण

1. अधिकांश मीडिया दलगत राजनीति से प्रेरित हैं।
2. सरकार की प्रतिकूल समीक्षा करने वाले मीडिया पर कार्यवाही, यह कारण हाल ही में अति चर्चित रहा है।

   पत्रकारों को कम वेतन का भी उल्लेख करें।
3. अधिकांश मीडिया चैनल औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित हैं, जिनका राजनीति से गठजोड़ है।
4. पत्रकारों की लालची प्रवृत्ति

वस्तुतः मीडिया की भूमिका अब सरकार की सहगामी या हिदान्वेषी हो गयी है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

के लिए सही नहीं है। मीडिया के अपने सही रास्ते पर चलने हेतु निम्न सुझाव जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दिए जा सकते हैं-

(1) इस अधिनियम के तहत राजनीति से प्रेरित न्यूज चैनलों द्वारा 'पेड न्यूज' प्रदर्शित किए जाने पर कठोर कार्यवाही हो। इसमें संलग्न नेताओं, प्रत्याशियों व पत्रकारों पर कठोर कार्यवाही हो।

(2) सभी चुनावी सर्वेक्षणों के लिए चुनाव आयोग द्वारा मानक तय हों, जैसे - सैंपल का आकार, सर्वेक्षणकर्ता पत्रकारों का प्रशिक्षण, सैंपल में शामिल वर्ग तथा उनकी संख्या। इस हेतु निगरानी हेतु चुनाव आयोग के तहत नियामक बनाया जा सकता है।

कुल मिलाकर, लोकतंत्र में मीडिया जनता की आवाज होता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता दी गई होती है, अतः 'पेड न्यूज' जैसी बुराई लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है।

पेड न्यूज के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें... शामिल ... की भी चर्चा करें

लोकपाल, सिविल सोसायटी का भी उल्लेख करें।

3 1/2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1/2	1	.25	—	.25	
Grade	B	B	C	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राज़ील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ब्राजील घोषणापत्र सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, नुकसान को कम करने पर केन्द्रित वैश्विक प्रयास है, इसमें भारत ने सक्रियता से वचनबद्धता प्रदर्शित की है, क्योंकि भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या में सड़क दुर्घटना एवं सर्वाधिक मौतों वाला देश है। आये दिन होने वाली रेल, सड़क दुर्घटना देश को झकझोरती रहती हैं, अतः यह अन्य किसी राष्ट्रीय आपदा से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, अतः यह एक राष्ट्रीय आपदा है, क्योंकि समुचित प्रयासों द्वारा नुकसान को रोका जा सकता है।

[Margin remark: संबंधित प्रावधानों की भी चर्चा करें]

[Margin remark: संबंधित आंकड़ों का भी समावेश करें]

ब्राजील घोषणापत्र को लागू करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयोजन से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लाया गया है, जिसके मुख्य प्रावधान

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

मिल है -

(1) अपात्र व्यक्तियों के लाइसेंस पर नियंत्रण किया जाएगा, लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी तथा टेस्ट देने के बाद ही लाइसेंस मिल सकेगा।

(2) सड़क पर होने वाली मौतों के लिए सड़क निर्माता भी जिम्मेदार होंगे, सड़क में किसी प्रकार का दोष की जिम्मेदारी निर्माता पर होगी।

(3) पुराने वाहनों को वापस लिया जाएगा।

(4) एक फंड बनाया जाएगा, जो दुर्घटना प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

कुल मिलाकर कहा जाए तो यह विधेयक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का उचित विधिक कदम है, किन्तु दुर्घटनाओं में कमी तभी आयेगी जब पुराने कानूनों के विपरीत इसका बेहतर क्रियान्वयन हो।

सारथी या वाहन जैसे मंचों का भी उल्लेख करें

अन्य प्रावधानों यथा, टैक्सी एग्रीगेटर, थर्ड पार्टी बीमा, किशोर द्वारा अपराध इत्यादि की भी चर्चा करें

चुनौतियों की भी चर्चा करें

3½

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

...पया इस स्थान में प्रश्न ...ख्या के अतिरिक्त कुछ ... लिखें।
...lease do not write ...ything except the ...uestion number in ...is space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

फिल्में अभिव्यक्ति का बेहतर माध्यम हैं, जिनको नियमित करने के लिए संसद ने इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952 पारित किया तथा इसके तहत भारतीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को फिल्मों को नियमित करने, विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने तथा आपत्तिजनक चीजों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई। इस अधिनियम के तहत बोर्ड फिल्मों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू करता है, जिसके तहत फिल्मों में काट छांट, दृश्य परिवर्तन या फिल्म प्रतिबंध भी करता है।

(सेंसरबोर्ड का कार्य ऐसा नहीं है)

चर्चा में रहने के कारण

(1) फिल्म उड़ता पंजाब में 'पंजाब' शब्द को लेकर बोर्ड की आपत्ति।

(2) अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री को 'हिंदू', 'हिंदुत्व' जैसे शब्दों के कारण अनुमति न देना

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

③ 'लिपस्टिक अंडर माइ बुर्का' को भारतीय संस्कृति विरोधी तथा 'इंदु सरकार' को आपातकाल के दृश्यों को लेकर आपत्ति।

पूर्व-सेंसरशिप के विरुद्ध तर्क व विवादित पक्ष

① यह अनुच्छेद 19(1) A के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, यह निर्देशक की रचनाशीलता को रोकने का प्रयास है तथा यह कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन है।

② वर्तमान में खुले इंटरनेट एवं पोर्नोग्राफिक साइटों तक आसान पहुँच सेंसरशिप को अप्रासंगिक बना देती है।

③ भारतीय समाज अपनी प्रकृति में जड़ नहीं, प्रगतिशील व खुला है, अतः आधुनिक परिवर्तनों के अनुसार फिल्मों की विषयवस्तु में परिवर्तन आना लाजमी है।

आलोचकों का तर्क है कि सरकार इसके जरिये अपनी विचारधारा फिल्मों पर थोपना चाह रही है।

(Examiner's remarks in margin: ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एवं चलचित्रों/फिल्मों के संबंध में चर्चा करें; कॉपीराइट के उल्लंघन के संदर्भ में भी चर्चा करें)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वहीं दूसरी ओर बोर्ड का मत है कि इन फिल्मों की विषयवस्तु भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाली व भ्रामक है।

उपरोक्त विवाद के संदर्भ में निम्न सुझाव आमंत्रित हैं -

1. भारतीय संस्कृति विविधता में एकता पर आधारित है, जहाँ विरोधी एवं नवीन बातों को जगह है, अतः ऐसे समय में जब खुले इंटरनेट ने सभी हदें लाँघ दी है, तब सेंसरशिप के जरिये 'संस्कृति बचाने' के नाम पर सृजनशीलता, नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार व निर्देशक के फिल्म निर्माण के अधिकार को रोकना उचित नहीं है।

2. बोर्ड का दृष्टिकोण 'संस्कृति' के संदर्भ में लचीलापन होना चाहिए, किन्तु राष्ट्रविरोधी, मित्र देशों के संबंधों, लोकव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली फिल्मों पर पूर्व सेंसरशिप आवश्यक है।

निष्कर्षतः बोर्ड को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा इस संदर्भ में श्याम बेनेगल समिति की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए।

प्रयास अच्छा है

व्यावहारिक सुझाव भी चर्चा करें।

5

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	·5	2	1½	·25	·25	·25	
Grade	A	A	B	B	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संसद भारतीय संविधान का अहम अंग है, जिसको विधायी शक्ति प्रदान की गई है और संविधान संशोधन की शक्ति (~~अनु~~ अनुच्छेद 368) के तहत ~~संसद~~ संविधान में आवश्यक ~~परि~~ संशोधन कर सकती है। संसद को अपने कामकाज के संबंध में नियम बनाने, संसदीय विशेषाधिकारों के निर्माण व उनके उल्लंघन पर दंड देने का अधिकार है। संसद सदस्यों व सदनों को विशिष्ट कार्य एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु विशेष उन्मुक्तियाँ प्रदान [अनुच्छेद 105] की गई है।

क्या-क्या उन्मुक्तियाँ स्पष्ट करें।

वर्तमान में संसद अपने मार्ग से विचलित सी नजर आ रही है, क्योंकि

① संसद की कामकाज के दिन व घंटों की संख्या घट रही है, संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं तथा उत्पादक

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कार्य अनुत्पादक बहसों में जाया हो रहा है।

(2) विपक्ष का काम केवल सरकार का विरोध एवं संसद के कामकाज को ठप करना रह गया है।

(3) सांसद सदन के नियमों का पालन नहीं करते। मिर्च स्प्रे, धक्का मुक्की, हाथापाई की घटनाएँ होती रहती हैं।

(4) संसद का कामकाज बढ़ रहा है, विधेयकों की प्रकृति जटिल हो रही है, वहीं सांसदों की 'होमवर्क' करने की प्रवृत्ति घट रही है। पर्याप्त चर्चा करे बगैर विधेयक पारित हो रहे हैं, जैसे जीव विविधता विधेयक मात्र 10 मिनट में पारित कर दिया तथा अधिकांश अनुदान की माँगो पर गिलोटिन का प्रयोग किया जा रहा है, सामान्यतः विधेयक धन विधेयक (आधार विधेयक) के रूप में पारित किए जा रहे हैं।

वर्तमान में संसद के कामकाज में उक्त बाधाएँ लोकतंत्र व संसदीय मर्यादाओं

संक्षिप्त चर्चा करें।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

इस स्थान में प्रश्न के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

दृष्टि The Vision
Copyright – Drishti The Vision Foundation

व मूलभावना के खिलाफ है तथा संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाती है।

वर्तमान समय में संसद के पास विशेषज्ञता का अभाव व उन्हें विशेषज्ञ संस्था की मदद अपेक्षित होता है, किन्तु इस संदर्भ में सचिवालय की मदद ली जा सकती है। किन्तु सांसदों का स्वच्छंद व्यवहार को रोकने हेतु पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं, यह स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक पक्ष-विपक्ष अपनी जिम्मेदारी न समझें।

वस्तुतः निगरानी आयोग को कागज की पारदर्शिता व संसद की निगरानी हेतु बनाया जा सकता है, किन्तु उससे ज्यादा जरूरी दलों व सांसदों का स्वनियंत्रण व संसद की मूल भावना को समझने की जरूरत ज्यादा है।

संसदीय कार्यवाहियों को नियंत्रित करने व सुगम बनाने संबंधी वर्तमान में विद्यमान कानूनों, नागरिक संस्थाओं, संसदीय समितियों की चर्चा करते हुए उसमें सुधार एवं पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी आवश्यकताओं की

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1½	.28		.25	
Grade		B	B				

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

भारतीय संविधान संघवाद का प्रावधान करता है, जिसमें राज्यों को केन्द्र के व एकजुट के समकक्ष माना गया है। किन्तु सभी राज्यों का आर्थिक हैसियत समान नहीं है, राज्यों का विभाजन अगड़े व पिछड़ों में होगया है अतः पिछड़े राज्यों को आगे ले जाने के लिए केन्द्र का विशिष्ट सहयोग आवश्यक है।

सभी राज्यों के बीच समानता हो तथा सभी राज्यों को समान आर्थिक अवसर मिलें, इस हेतु ऐसे राज्यों जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास में आड़े आती हैं या जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, के विकासार्थ विशेष दर्जा राज्यों को प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह दर्जा पूर्वोत्तर के आठ राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को प्राप्त है।

उद्देश्य के तहत सांस्कृतिक, जातीय व राजनैतिक हितों के संरक्षण का भी उल्लेख करें।

गलत तथ्य न लिखें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright - Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

विशेष दर्जे के तहत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में इन राज्यों को 10% योगदान करना पड़ता है तथा शेष सरकार अनुदान देती है तथा आयकर कानून में विशेष छूटें प्राप्त होती हैं।

विशेष दर्जे की माँग से लाभ को देखते हुए बिहार, राजस्थान, और अब तेलंगाना, आँध्रप्रदेश द्वारा माँग की जा रही है, यहाँ इसके लिए जन आंदोलन भी हुए हैं।

यह बात सत्य है कि विशेष राज्य दर्जे से राज्यों को लाभ मिलता है, किन्तु यह समस्या व्यापक इसलिए हुई है क्योंकि सरकार राजनीतिक रूप से राज्यों को स्वैच्छिक अनुदान (वित्त आयोग की अनुशंसा से इतर) देती है, वही कुछ और विशेष दर्जे से मिलता है। इसलिए जो

आमसहमति अन्य प्रावधानों की भी चर्चा करें। दोनों के तहत अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना के विकास की भी चर्चा करें। हालिया हुई घटनाओं के तहत जम्मू कश्मीर, प. बंगाल, असम, नागालैंड इत्यादि की भी चर्चा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

राज्य पिछड़े रह गये हैं तथा जिन्हें केन्द्र से न अनुदान मिला है, वहाँ विकासार्थ आर्थिक मदद की माँग करना आवश्यक है।

किन्तु वर्तमान में यह माँग अप्रासंगिक प्रतीत हो रही है क्योंकि वर्तमान में 42% कर का वितरण राज्यों को हो रहा है।

हाँ, यह किया जा सकता है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले विशेष पैकेज तार्किक हों, तथा पिछड़ों के लिए मददगार हों न कि अपने दल की राज्यों में सरकार को मदद करने का हथियार।

वाक्य संरचना पर ध्यान दें

B

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1	1	.25	—	.25	
Grade	B	C	C	B		B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

वर्तमान में न्यायिक सेवा कई समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें कार्य का बढ़ता बोझ, समय पर न्यायधीशों की नियुक्ति नहीं, रिक्त पद, न्यायधीशों की गुणवत्ता का अभाव, युवाओं व वार सदस्यों का राज्य न्यायिक सेवाओं से मोहभंग। इस संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सुझाव दिया जाता है, जिसको यूपीएससी आयोजित करेगा तथा जो राज्य की न्यायिक सेवाओं की जगह लेगी।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत क्यों?

1. सिविल सेवकों की तरह समय पर न्यायधीशों की नियुक्ति, अखिल भारतीय स्तर के युवाओं का न्यायिक सेवा की ओर आकर्षण व बेहतर प्रशिक्षण व वेतनमान
2. राष्ट्र की एकता में भूमिका क्योंकि अन्य राज्य के न्यायधीश दूसरे राज्य में होंगे।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मार्ग में समस्याएँ
① ~~कुछ कोर्ट~~ में राज्य तैयार नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति में कटौती होगी।
② सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उत्साहजनक नहीं।

कुल मिलाकर, वर्तमान की अनेकों समस्याओं का हल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, जो शीघ्र, प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

1½

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

न्याय प्रक्रिया के बोझ को न्यायपालिका से कम करने तथा विशेषज्ञ न्याय दिलाने हेतु 42वें संविधान संशोधन, 1976 के तहत ~~अनुच्छेद~~ न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया।

वर्तमान में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों ने न्यायपालिका के बोझ को कम किया है किन्तु इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कई समस्याएँ उत्पन्न कर रही है -

1. कार्य का अतिव्यापन, ~~विवाद~~ उलझाव, IRDA तथा EPFO का टकराव।

2. ~~अधिकरण~~ न्यायपालिका के कार्यों को प्रशासन को ~~सौंपता~~ सौंपता है अतः प्रत्यायोजित न्यायन ~~शक्ति~~ पृथक्करण के खिलाफ है।

3. ज्यादा न्यायाधिकरणों से सहयोग व एकीकृत कार्यवाही मुश्किल होती है।

4. चूँकि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में प्रशासन ही प्रशासन की जाँच करता है, क्योंकि अधिकांश मामले सरकार से संबंधित होती हैं। अतः भाई भतीजावाद व पक्षपात की संभावना रहती है।

वर्तमान में ~~न्याय~~ की तकनीकी होती प्रकृति को देखते हुए ~~न्याय~~ अधिकरण आवश्यक है, किन्तु इसका प्रशासनिक ~~अभाव~~ पैदा करने वाला न हो, अन्यथा भविष्य में सीमित न्यायाधिकरणों के एकीकरण जैसे प्रयास करने पड़ेंगे।

(Examiner's marginal notes: ↳ कार्य क्षमता में कमी; ↳ निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील; ↳ पेंडिंग मामलों में अत्यधिक वृद्धि; ↳ शक्ति पृथक्करण का भी उल्लंघन करें; सुझावों के तहत: ✗ स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन; ✗ सभी न्यायाधिकरणों को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया जाए; 1½)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान मे कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

लोकतंत्र के एक संस्था के रूप में सुचारु संचालन ~~से संबंधित~~ के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जरुरी हैं। किन्तु वर्तमान में धनबल का बढ़ता प्रयोग, क्रोनी कैपीटलिज्म ने लोकतंत्र की भावना को नुकसान पहुँचाया है, अज्ञात चंदे के कारण 'समान चुनाव अवसर' का प्रभावित हुआ है।

हाल ही में चुनावों ~~की~~ के निष्पक्ष क्रियान्वयन व अवैध चंदे पर नियंत्रण लाने व पारदर्शिता बढ़ाने हेतु कुछ उपाय लाए गए हैं-

(1) एक व्यक्ति से अधिकतम 2000₹ का चंदा लेना।

(2) पूरा चंदा चैक में या डिजिटल।

(3) दलों के वित्तपोषण हेतु चुनावी बॉण्ड।

→ ADR रिपोर्ट का भी उल्लेख करें

→ नकद चंदे की सीमा 2000
→ चुनावी बांड संबंधी समयसीमा का भी उल्लेख करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

दृष्टि The Vision

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(4) आयकर अधिनियम की छूटों का लाभ लेने के लिए रिटर्न भरना।

गौरतलब है कि भारत जैसे देश में 2000 की चंदे की सीमा भी अवैध चंदे का अवसर प्रदान करती है, बशर्ते अब और लोगों को शामिल करना होगा, जो कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि दलों के लिए दानदाताओं के नाम बताना जरूरी नहीं है।

चुनावी बॉण्ड में कौन जानता है अधिक औद्योगिक घरानों के निवेश की ~~उम्मीद~~ आशंका ज्यादा है।

किन्तु, ये प्रयास वित्तीय पारदर्शिता के लिए अहम हैं क्योंकि चुनाव आयोग लंबे ~~समय~~ से 2000 ₹ सीमा तय करने की माँग कर रहा था।

किन्तु ये कदम नाकाफी हैं। दलों की ~~राजनैतिक~~ जवाबदेही हेतु निम्न कदम उठाये जाए -

- दलों का सूचना के अधिकार के दायरे में न होना
- कुछ धन की ऊपरी सीमा का निर्धारण नहीं किया है।
- इत्यादि की भी चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

(1) अमेरिका की तरह सभी दलों को दानदाताओं के नाम पता करना तथा उन्हें जनता के समक्ष रखना अनिवार्य हो।

(2) दाताओं की सूची को आयकर विभाग के पास दिया जाए तथा दाताओं का आधार लेना अनिवार्य हो।

(3) एक स्वतंत्र संस्था द्वारा दलों के खातों की आडिट हो व रिपोर्ट को जनता के समक्ष रखा जाए।

(4) राज्य वित्त पोषण को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष :- चूँकि अज्ञात चंदा ज्यादातर कार्पोरेट घरानों से होता है, किन्तु इसका पता नहीं लग पाता है, जबकि वे सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, अतः दलों की जनजवाबदेही आवश्यक है। अतः चंदे में पारदर्शिता लाने संबंधी प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए।

RTI के दायरे में लाना
→ कारपोरेट प्रभाव पर नियंत्रण
→ सरकार द्वारा ... माध्यम से ...
→ 2000 रु. तक भी ...
इत्यादि किसी भी चर्चा करें

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1	.25	—	.25	✓
Grade	B	B	C	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द) 12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कालेधन से तात्पर्य वह धन है जिस पर कर अदा नहीं किया गया है। 'अचल संपत्ति क्षेत्र' कालेधन के नियोजन का अहम क्षेत्र बनकर उभरा है क्योंकि बड़ी रकम को भौतिक एवं डिजिटली रखना संभव नहीं होता अतः लोग अपने या अपने सगे संबंधियों व मित्रों के नाम से अचल संपत्ति खरीद कर धन को प्रयुक्त करते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं आवास हेतु शहरी गरीबी उन्मूलन की रिपोर्ट का भी उल्लेख करें

अचल संपत्ति क्षेत्र में सुधार लाने हेतु हाल ही में अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान व लाभ निम्न हैं –

कब?

(i) RERA के तहत अचल संपदा विनियमन

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसके तहत बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का नामांकन, निर्माण की जानकारी, इस क्षेत्र में संलग्न का सत्यापन करवाना तथा उपभोक्ताओं से जुटाए धन की जानकारी अनिवार्यता में देनी होगी। तथा किसी भी अनियमितता में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही होगी, जो उपभोक्ता हितों को फायदा पहुँचाएगी।

(2) RERA के तहत एक विशेष एस्क्रो अकाउंट में परियोजना का 70% धन प्राधिकरण की निगरानी में जमा कराना होगा, जो प्रतिबद्ध रहेगी अतः भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी एवं उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी रुकेगी।

(3) इस अधिनियम के तहत किसी भी उपभोक्ता शिकायत का 60 दिनों में निवारण कर समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) फ्लैट देने के बाद भी 5 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार की कमी की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी।

अधिनियम से चुनौतियों की भी चर्चा करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

(5) वित्तीय अनियमितता एवं कानून के उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंडात्मक प्रावधान किए हैं।

कुल मिलाकर यह अधिनियम अचल संपत्ति क्षेत्र को बेहतर नियमन प्रदान करेगा जो अभी तक नियमन से बाहर था जिसके चलते उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, जिसके कम होने की उम्मीद है।

3½

संक्षेप में लिखें

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1¼	.25	—	.25	✓
Grade	B	B	B	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

भारत में न्यायपालिका ~~विशेष~~ लोकतंत्र व संविधान के सुचारु संचालन के लिए अहम है। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है तथा ~~न्याय~~ विधायिका के किसी ~~भी~~ संविधान विरोधी कृत्य को रोकती है। अतः ~~भारतीय~~ संविधान ने न्यायपालिका को विशेष शक्तियाँ प्रदान की हैं।

अनुच्छेद 142 भारत में पूर्ण न्याय के लिए ~~न्याय~~ सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी भारतीय न्यायक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाने, अपने फैसले लागू करने तथा किसी भी प्रकार की अवमानना पर दंड देने

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

की शक्ति प्रदान करता है।

हाल के दिनों में पूर्ण न्याय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, जो उसके दायरे में नहीं है। उदाहरण के लिए सड़क किनारे शराब के ठेकों को हटवाना व, मेडिकल परीक्षा आयोजित करवाने हेतु निर्देश देना।

हाल के दिनों में अनुच्छेद 142 चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया तथा पेश न होने पर न्यायालय की अवमानना मानकर उनको दंडित

सकारात्मक पक्ष
↳ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हित की रक्षा
↳ ताज महल की सुरक्षा
↳ विचाराधीन कैदियों की रिहाई
इत्यादि की चर्चा करें

नकारात्मक पक्ष की भी चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

इस स्थान में प्रश्न के अतिरिक्त कुछ [न लिखें]। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

किया गया।

वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक तथा मूल अधिकारों की गारंटीदाता है अतः पूर्ण न्याय के द्वारा किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार आवश्यक है।

1½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	½	½	.25	—	—	
Grade	D	D	D	B			

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ है, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

वर्तमान समय ~~विज्ञान~~ तकनीक का है, नवीन प्रयोगों का है, पुरानी सभी समस्याओं का समाधान नये तरीके से ढूँढा जा रहा है। अतः सेवाओं तथा नीतियों की प्रभावी पहुँच के लिए आधार जैसे नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है।

वर्तमान समस्याओं की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता को बढ़ाये जाने की विश्लेषण करें।

आधार क्यों जरूरी

1. आधार के माध्यम से केन्द्र द्वारा दिये 1 रुपये में से पूरा 1 रुपया पहुँचाना संभव हुआ है। जबकि राजीव गाँधी के अनुसार केन्द्र का 1 रुपया गरीब तक 15 पैसे के रूप में पहुँचता।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(२) आधार लिंकिंग जनधन-मोबाइल-आधार त्रिमूर्ति ने गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद की है। मनरेगा, उज्ज्वला योजना, LPG सब्सिडी सुविधा आदि सीधे गरीबों के खाते में पहुँच रही है।

(3) आधार कार्ड पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार रोकने का अहम हथियार है। आयकर रिटर्न के साथ संयुक्त कर कर अपवंचन को रोका जा सकेगा।

किन्तु दूसरी ओर आधार को प्रत्येक सेवा में लागू करने से विभ्रम व मानसिक अलगाव की समस्या पैदा हुई है। ऐसे देश में जहाँ लोगों की बैंकों तक समावेशी पहुँच नहीं है, वहाँ सभी योजनाओं को आधार से जोड़ना, उन्हें सेवाओं से दूर कर ऐसे लोगों को सर्वाधिक देगा, जबकि जरूरत ऐसे लोगों को सर्वाधिक है, जैसे - दुर्गम क्षेत्रों के आदिवासी। साथ ही आधार में महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, यदि इसका प्रशासनिक

निजता, व्यवसाय, सुरक्षा का भी उल्लेख करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उपयोग हुआ, तो व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी सरकार के पास होना निजता का उल्लंघन है।

किन्तु, सार यह है कि आधार पारदर्शिता, जवाबदेहिता व योजनाओं की प्रभावी पहुँच के लिए आवश्यक है, किन्तु इसके मार्ग में चुनौतियाँ हैं, सरकार को निजी को आधार से जोड़ने तथा वित्तीय समावेशन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए तथा नागरिकों का डाटा सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों से सुरक्षित हो, जिसकी एक संसदीय समिति आवधिक निगरानी करे।

→ इंटरनेट की समस्या
→ विद्युत आपूर्ति की समस्या
→ बैंक खातों के उपयोग में ... इत्यादि की भी चर्चा करें।

→ लोगों की शंकाओं का निराकरण
→ कर्मचारियों को प्रशिक्षण का भी उल्लेख करें।

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1	.25		.25	✓
Grade	B	B	C	B		B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

भारत में महिलाओं की श्रम में भागीदारी पहले से ही कम रही है। किन्तु वर्तमान में NSSO के आंकड़े बताते है कि एक ओर जहाँ शहरों में महिला श्रमबल की भागीदारी बढ़ नहीं रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या कम हो रही है।

[आंकड़ो का उल्लेख करें]

शहरी क्षेत्र में महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी न बढ़ने के कारण

[वास्तविक स्थिति, अनुकूल आर्थिक, जनांकिकीय स्थिति की चर्चा करें]

① शहर में महिलाओं ~~की~~ विशेषतः मध्यमवर्गीय परिवारों में, की भूमिका को गृहणी के रूप में देखा जाता है, जबकि पुरुष को आर्थिक कार्य करने वाला। अतः महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उन्हें कार्य करने

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

की अनुमति नहीं देती या पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है।

(2) वर्तमान में डिजिटलीकरण में ऑटोमेशन का बढ़ता प्रयोग, रोबोटिक्स व कृत्रिम बुद्धिमता जैसे कारणों से नौकरियाँ उत्पन्न नहीं हो रही है, अतः नौकरियाँ घट रही है।

(3) महिलाओं को विनिर्माण विशेषतः भारी उद्यमों में नियोजित नहीं किया जाता। तथा मातृत्व अवकाश जैसे प्रावधानों के चलते नियोक्ता महिलाओं को रोजगार देने में झिझकते है।

(4) महिलाओं में उद्यमशीलता, कौशल का अभाव एक कारण है।

गाँवों में महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी घटने के कारण

(1) गाँवों में कृषि महिलाओं के

→ पुरुष वर्ग की शिक्षा व अर्थ...
→ शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि
→ सुरक्षा इत्यादि की भी चर्चा करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

नियोजन का प्रमुख होते है, जबकि आज कृषि घाटे का सौदा होने से कृषि छोड़ने की दर (बढ़) रही है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में उन उद्यमों का अभाव है, जो महिलाओं के लिए पारंपरिक तौर पर उचित माने जाते हैं, जैसे - साड़ी निर्माण।

(3) ग्रामीण महिलाओं के पास कौशल का अभाव

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में माँग का अभाव नये रोजगारों को जन्म नही दे रहा है।

अतः महिलाओं की श्रमबल में गिरावट भागीदारी न बढ़ना व ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का कारण है. सरकार को स्वयंसहायता समूहों, संस्थागत वित्तपोषण, विशेष प्रोत्साहन योजनाओं को चलाने की दरकार है, ताकि सामाजिक समावेशन व लैंगिक न्याय की प्राप्ति हो सके।

अच्छा प्रयास

A

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1 1/2	1 1/2	.25	—	.25	
Grade	B	B	B	B		B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है अपने धर्म संबंधी गुण को व्यक्तिगत स्तर पर सीमित रखना तथा सार्वजनिक मामलों व सामाजिक संबंधों में धर्म को बीच में न लाना। इस लिहाज से देखें तो अशोक का धम्म, अकबर का दीन ए इलाही, गंगा जमुनी तहजीब, भारतीय राजाओं की सहिष्णु नीतियाँ व धार्मिक आधार पर जनता के साथ भेदभाव न करना भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्षता को उद्घृत करता है।

सराहनीय प्रयास

हाल ही के दिनों में धर्मनिरपेक्षता को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह विशेष धर्म को बढ़ावा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दे रही है जबकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का अहम् अवयव है। वर्तमान में गौहत्या का मामला व गौहत्या व गौमांस पर भीड़ के हमले, हिन्दु संस्कृति को तथाकथित रूप से ओढ़ने के आरोप आदि धर्मनिरपेक्षता को चर्चा के केन्द्र में ले आए हैं।

संविधान के भाग में धर्मनिरपेक्षता को विभाषित करें

मीडिया की भूमिका स्पष्ट करते हुए और अन्य मुद्दे अन्य उदाहरणों का भी उल्लेख करें।

किन्तु भारतीय समाज के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ये घटनाएँ जितनी हैं उससे अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित की जा रही हैं। भारतीय समाज अपनी मूल प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष ही है, जिसका आधिकारिक गुण सहिष्णुता है। वर्तमान भारत ध्रुवीकरण व सामाजिक लोक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी अपने हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। किन्तु यह बात भी

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

सत्य है कि धर्म को लेकर समाज में टकराव बढ़ा है।

किन्तु धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक स्तर पर बनाए रखना जरूरी है, सरकार को ऐसी सभी प्रयासों को विफल बनाना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुँचाते हैं तथा राज्य को न तो किसी धर्म के प्रति आग्रह, न किसी धर्म के प्रति दुराग्रह, न किसी को विशेष फायदा व न किसी को नुकसान पहुँचाना चाहिए। बल्कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता बनाए रखनी संभव करनी है।

भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए धर्मनिरपेक्षता की सफलता की चर्चा करें

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.5	1	1	.25	–	.25	✓
Grade	A	C	C	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

वर्तमान में भारतीय कृषि संरचना संक्रमण के दौर में है, अब कृषि व्यवसाय से कृ० लागत निकालने में भी मुश्किल हो रहा है, जिससे किसानों की दुर्दशा होती जा रही है, जिसके लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं-

(1) कृषि की बढ़ती लागत व स्थिर उत्पादन

(2) कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना, उदाहरण के लिए समाचार पत्रों में सड़क किनारे आलू फेंके जाने की खबर।

(3) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बीमा सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

(4) खेती पर अत्यधिक निर्भरता, जरूरत से ज्यादा श्रमबल।

(5) कृषि के साथ अन्य वैकल्पिक रोजगार का अभाव

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की चर्चा करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(6) संस्थागत वित्त तक पहुँच का अभाव।

(7) कृषि की मानसून पर निर्भरता व मानसून की अनिश्चितता, जैसे कावेरी बेसिन क्षेत्र में कर्नाटक व तमिलनाडु के किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन।

खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसानों की सुरक्षा आवश्यक है, इस संदर्भ में चर्चा करें

कृषि की संकटपूर्ण स्थिति ने किसान के समक्ष आजीविका, गरिमापूर्ण जीवन जीने का संकट खड़ा कर दिया है, जिससे निजात पाने के लिए किसान आत्महत्या करता है।

किसानों की दशा सुधारने के लिए निम्न प्रयास अपेक्षित हैं -

खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली चुनौतियाँ स्पष्ट करते हुए सुझाव दें।

(1) न्यूनतम समर्थन मूल्यों को तार्किक कर तथा ऑनलाइन कृषि मंडी तक किसानों की पहुँच बढ़ाकर, उचित मूल्य दिया जाए।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(२) प्रधानमंत्री ~~फ~~ फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड से संस्थागत वित्त प्रदान करना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना को तेजी से लागू किया जाए, ताकि किसानों कृषि की लागत कम हो।

(3) कृषि से संबंधित मशीनों को सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराने।

(4) गाँवों में सहकारी कृषि को बढ़ावा मिले, ताकि किसानों की लाभप्रदता बढ़े।

निष्कर्षतः किसानों की 2022 तक आय दुगुनी करने के लिए उठाये कदमों को जमीन पर उतारा जाए, क्योंकि भारत के गरीबी निवारण का रास्ता किसान कल्याण से ही गुजरता है।

प्रश्न की माँग के संदर्भ में उत्तर में भटकाव अधिक है।

1

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	—		1	—			
Grade			C				

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

दृष्टि The Vision

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

परिवार भारतीय समाज की अहम इकाई है। प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज में परिवार की संयुक्त प्रथा रही है, किन्तु वर्तमान में संयुक्त परिवार एकल परिवार और 1990 के बाद न्यूक्लीयर परिवारों में परिणत हो रहे हैं।

संयुक्त परिवार की धारणा टूटने में सर्वाधिक योगदान व्यक्तिवाद की बढ़ती भावना का रहा है। महिलाओं का संयुक्त परिवारों में अत्यधिक शोषण होता है अतः उनकी इच्छा एकल परिवार में होती है, युवाओं

ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात परंपरागत परिवार व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करें; आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक परिवर्तन प्रथा => आर्थिक प्रणालियों इत्यादि

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

की सोच अधिकतम संवेदना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर है जो संयुक्त परिवार में संभव नहीं।

किन्तु संयुक्त परिवार टूटने का व्यक्तिवाद एक कारण है, इसके अन्य कारण भी हैं -

(1) व्यापार वाणिज्य के अवसरों का व्यापक होना। सेवा क्षेत्रक के कामगारों को जगह जगह काम करना होता है अतः यह एकल परिवार को बढ़ावा देता है।

(2) भारत में गाँवो से शहरो की ओर पलायन बढ़ रहा है, जिसमें पुरानी पीढ़ी गाँव में ही रहना चाहती है।

(3) पारिवारिक मूल्यों जैसे एक व्यक्ति के निजता (सुविधा) में रहना, का आग्रहशील होना।

औद्योगीकरण
⇒ शिक्षा
> पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
> विवाह व्यवस्था
> सामाजिक धार्मिक इत्यादि की भी चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारतीय समाज अपनी प्रकृति में गतिशील रहा है और आधुनिकता ने संयुक्त परिवारों को टूटने के लिए मजबूर बना दिया है। जिनके बच्चों एवं बुजुर्गों पर भावनात्मक अकेलापन जैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किन्तु महिलाओं पर प्रभाव सकारात्मक रहा है।

वास्तव: भारतीय परिवार विशेष स्थिति में हैं जहाँ भौगोलिक तौर पर परिवार टूट गये हैं किन्तु कार्यात्मक तौर पर संयुक्त हैं, अतः संयुक्त परिवारों का टूटना कोई विशेष नकारात्मक असर समाज में नहीं लाया है।

भारतीय सामाजिक समुदाय → आधुनिकता → परम्परा निर्भरता → इत्यादि का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1	1	.28	—	.28	
Grade	B	C	C	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत में कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में विशेष समस्या रही है कि जिन अनुरूप योजनाएँ बनाई जाती हैं, उनका लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाता। योजनाओं में बीच में लीकेज उन्हें अप्रभावी बना देता है तथा ही जिन स्तर की योजनाओं के लिए वित्त की जरूरत होती है, वह भी अपर्याप्त होता है।

इस संदर्भ में विमुद्रीकरण ने भारतीय समाज में वित्तीय जागरूकता का समावेश किया है, विमुद्रीकरण विभिन्न प्रकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएगा। – क्रियान्वयन

(हाशिये पर टिप्पणी: विमुद्रीकरण कब किया गया उल्लेख करते हुए इसके उद्देश्य स्पष्ट करें)

(हाशिये पर टिप्पणी: → बिचौलियों की समस्या → आधारहीन लाभार्थी इत्यादि का भी उल्लेख करें)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

① विमुद्रीकरण ने कैशलैस सोसाइटी की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। यह कालेधन की अर्थव्यवस्था पर रोक लगाएगा। कैशलैस होने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आसान होजाएगा। लोग अपना कर अपवंचन नहीं कर पाएंगे, जो सरकार के लिए प्रभावी राजस्व सृजन में मदद करेगा। इससे कल्याणकारी योजनाओं को पर्याप्त वित्त प्राप्त होगा तथा उसकी पूरी मदद सीधे वंचितों को प्राप्त होगी (जैम-त्रिमूर्ति के प्रयोग से)

② कैशलैस सोसाइटी डिजिटल समाज होता है, जो ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार तक प्रभावी पहुँच रख पाएगा।

③ विमुद्रीकरण से कैशलैस सोसाइटी निर्मित होने से पूरा धन अर्थव्यवस्था में चक्रीय रूप से घूमता रहेगा जो जीडीपी वृद्धि को बढ़ाने में अहम होगा।

→ बिचौलियों का उन्मूलन
→ समयानुसार निधि का वितरण
→ [illegible] लाभार्थियों का उन्मूलन इत्यादि की भी चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(4) कैशलेस अर्थव्यवस्था को साकार बेहतर तरीके से नियोजित कर पायेगी।

कुल मिलाकर विमुद्रीकरण ने कैशलेस सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाकर योजनाओं को प्रभावी बनाने की ओर कदम तो बढ़ाया है, किन्तु डिजिटल खाई, सभी की इंटरनेट तक पहुँच, डिजिटल शिक्षा को बढ़ाना, साइबर सुरक्षा जैसे कार्यों को जब तक पूरा किया जाना बाकी हो जब तक पूरा समाज 'कैशलेस' न हो, तब तक 'लेसकैश' की तरफ बढ़ा जा सकता है।

सराहनीय प्रयास

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	·25	1½	1	·25	—	·25	
Grade	B	B	C	B		A	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

हाल ही के दिनों में उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में किसानों की माँग पर ऋणमाफी की गयी जो राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में भी माँग पकड़ने लगी है। कृषि ऋण माफी के तहत सरकार एक निश्चित मात्रा से नीचे के बैंकिंग ऋणों को माफ कर देती है।

कृषि ऋणमाफी अस्थायी क्यों?

(1) कृषि की मूल समस्या कृषि का लाभदायक न रह जाना है। जब तक कृषि लाभप्रद न होगी तब तक किसान ऋणग्रस्त ही रहेंगे।

(2) कृषि की मूल समस्या उपज का सही मूल्य न मिलना, मानसून की अनिश्चितता व बीमा का अभाव, कृषि उपकरण व खाद बीजों का महंगा होना, जिससे लागत बढ़ना

[Examiner's remarks in margin: भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ऋणमाफी योजना के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करें। नकारात्मक पक्ष और स्पष्ट करें। निष्कर्ष में और भावी ... दें।]

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

तथा दूसरी ओर उपज में वृद्धि न होना है। जिससे किसानों की माल गिर रही है।

③ मूल जरूरत कृषि में निवेश बढ़ाने की है।

~~सरकार योजनाओं के लाभ~~

अतः यह तो स्पष्ट है कि भारतीय कृषि का सरकारी समर्थन की जरूरत है। क्योंकि कृषि के संकट में आने का कारण सरकार का पर्याप्त ध्यान का अभाव है। योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। अतः दीर्घकालिक उपाय यही है कि सरकार कृषि में निवेश बढ़ाए, उपज का पर्याप्त मूल्य दे, किसानों की आय को दुगुनी व लागत को आधी करे तथा भूमि सुधार को यथाशीघ्र लागू करे।

किंतु जब तक ऐसे उपाय नहीं हो तब तक अस्थायी राहत के रूप में राहत माफी जैसे कल्याणकारी कदम उठाने

संक्षेप में और माफी यों करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

जा सकते हैं, किन्तु वे बारबार नहीं होने चाहिए।

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	·25	1/2	1/2	·25	—	·25	
Grade	B	D	D	B		B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation